

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्रसारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, करवरी 3, 1976/माघ 14, 1897

नो. 61]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 1976/MAGHA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

### MINISTRY OF LABOUR

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February 1976

S.O. 76(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Food Corporation of India engaged in the foodstuffs industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the Food Corporation of India to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/10/75-D.IA]

D. BANDYOPADHAY, Jt. Secy.

## श्रम मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1976

का० आ० 76 (अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि खाद्य पदार्थों सम्बन्धी उद्योग में लगे भारतीय खाद्य निगम, जिसे श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[[संख्या एस-11017/10/75-डी० I-ए]]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव।